स्टेबल कॉइन, सीबीडीसी और भारत की विकसित होती मौद्रिक संरचना

यूपीएससी प्रासंगिकता-

- **प्रारंभिक परीक्षा-कीवर्ड**: **स्टेबल कॉइन, सीबीडीसी, क्रिप्टोकरेंसी विनियमन, डिजिटल भुगतान, मौद्रिक संप्रभुता, फिनटेक नवाचार, वैश्विक पूंजी प्रवाह**
- **मुख्य परीक्षा-जीएस पेपर 3: अर्थशास्त्र, बैंकिंग, मौद्रिक नीति, वित्तीय प्रौद्योगिकी**

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2025 में अपने संबोधन में वैश्विक वित्त पर स्टेबलकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी नवाचारों के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला।
- उन्होंने कहा कि देशों को नई मौद्रिक संरचनाओं या जोखिम बहिष्करण के अनुकूल होना चाहिए। उन्होंने भारत की क्रिप्टोकरेंसी नीति में संभावित बदलाव का संकेत दिया और वित्तीय संप्रभुता बनाए रखने में सीबीडीसी (केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा) की भूमिका पर ज़ोर दिया।

पृष्ठभूमि: क्रिप्टो नवाचार और वैश्विक मौद्रिक परिवर्तन

स्टेबलकॉइन:

- क्रिप्टोकरेंसी स्थिर परिसंपत्तियों जैसे फिएट मुद्राओं या सोने से जुड़ी होती हैं।
- **उदाहरण:** USDT (Tether), USDC, DAI
- **उद्देश्य:** अस्थिरता को कम करना, डिजिटल भुगतान और सीमा पार लेनदेन को सक्षम बनाना।

Result Mitra रिजल्ट का साथी
www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

निजी क्रिप्टोकरेंसी:

- अत्यधिक अस्थिर, कानूनी निविदा स्थिति का अभाव।
- वर्तमान में भारत में वैध नहीं हैं, लेकिन लेनदेन पर कर लगाया जाता है।

सीबीडीसी (CBDC):

- भुगतान को आधुनिक बनाने और मौद्रिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए आरबीआई द्वारा संचालित।
- कानूनी समर्थन वाली सरकार द्वारा जारी डिजिटल मुद्राएँ।

वैश्विक वित्तीय प्रणाली प्रणालीगत परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जिससे राष्ट्रों के लिए आर्थिक प्रभाव बनाए रखने हेतु अनुकूलन आवश्यक हो गया है।

परिवर्तन का पैमाना

1. राष्ट्रों के लिए द्विआधारी विकल्प

देशों के सामने दो विकल्प हैं:

- स्थिर मुद्रा और डिजिटल परिसंपत्तियों जैसी नई मौद्रिक संरचनाओं के अनुकूल होना, या
- विकसित हो रहे वैश्विक वित्तीय नेटवर्क से जोखिम बहिष्करण।

अनुकूलन न करने से पूँजी प्रवाह, व्यापार वित्त और सीमा-पार भुगतान में प्रभाव कम हो सकता है।

2. वैश्विक संदर्भ

- वित्तीय नवाचार पारंपरिक बैंकिंग और पूँजी आवंटन सहित मुद्रा के परिदृश्य को नया रूप दे रहे हैं।
- रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता, युद्ध और उभरते गठबंधन पुराने गठबंधनों की परीक्षा ले रहे हैं और नई साझेदारियों के अवसर पैदा कर रहे हैं।

उदाहरण: डिजिटल भुगतान और स्थिर मुद्रा को एकीकृत करने वाले देश तेज़ प्रेषण और सीमा-पार व्यापार को सुगम बनाने में सक्षम हैं, जिससे उन्हें गैर-अपनाने वालों पर बढ़त मिलती है।

भारत का वर्तमान दृष्टिकोण

1. निजी क्रिप्टोकरेंसी / आभासी डिजिटल परिसंपत्तियाँ (VDA)

- वैध नहीं हैं, लेकिन लेनदेन पर कर लगता है।
- आरबीआई ने अस्थिरता, धोखाधड़ी के जोखिम और धन-शोधन संबंधी चिंताओं के कारण प्रतिबंधों की वकालत की है।

2. केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC)

- आरबीआई द्वारा जारी और विनियमित, पूरी तरह से वैध मुद्रा।

पायलट परियोजनाएँ चल रही हैं:

- डिजिटल भुगतान का आधुनिकीकरण,
- नकदी पर निर्भरता कम करना, और
- निजी क्रिप्टो वृद्धि के महेनजर मौद्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करना।

3. आर्थिक उत्तोलन और लचीलापन

- भारत में बाहरी झटकों को झेलने की प्रबल क्षमता है।
- रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए वित्तीय और भू-राजनीतिक सतर्कता आवश्यक है।

सीतारमण के शब्द:

"रणनीतिक स्वतंत्रता की कीमत शाश्वत प्रदर्शन है।"

चुनौतियाँ

1. नियामक अनिश्चितता:

- निजी स्थिर मुद्राओं और क्रिप्टोकरेंसी में स्पष्ट कानूनी ढाँचे का अभाव है, जिससे निवेशकों और वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा होते हैं।

2. वित्तीय संप्रभुता जोखिम:

- निजी स्थिर मुद्राओं को व्यापक रूप से अपनाने से राष्ट्रीय मुद्रा नियंत्रण कमजोर हो सकता है।

3. वैश्विक प्रतिस्पर्धा:

- डिजिटल परिसंपत्तियों से जुड़े न रहने वाले देशों को सीमा-पार डिजिटल वित्तीय प्रणालियों से बहिष्कृत किया जा सकता है।

भारत के लिए आगे का रास्ता

1. संतुलित नीति दृष्टिकोण:

- नवाचार को बाधित किए बिना निजी क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करें।
- मौद्रिक संप्रभुता बनाए रखने के लिए CBDC को अपनाने को बढ़ावा दें।

2. स्थिर मुद्राओं के साथ रणनीतिक जुड़ाव:

- वैश्विक स्थिर मुद्रा पहलों की निगरानी, एकीकरण या सहयोग के लिए ढाँचों का अन्वेषण करें।

3. आर्थिक लचीलापन मज़बूत करें:

- वैश्विक मौद्रिक बदलावों से निपटने के लिए वित्तीय सतर्कता, नियामक स्पष्टता और रणनीतिक योजना को एक साथ लाएँ।

4. जन जागरूकता और नवाचार:

- क्रिप्टोकरेंसी पर डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करें।
- विनियमित और सुरक्षित ढाँचों के तहत फिनटेक नवाचार का समर्थन करें।

निष्कर्ष

भारत मौद्रिक परिवर्तन के चौराहे पर खड़ा है:

- स्टेबलकॉइन जैसे नवाचार वैश्विक स्तर पर पूंजी प्रवाह को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं।
- सीबीडीसी कानूनी निश्चितता प्रदान करते हैं और राष्ट्रीय नियंत्रण बनाए रखने में मदद करते हैं।
- आर्थिक संप्रभुता की रक्षा के लिए, भारत को एक संतुलित नीति अपनानी चाहिए, नवाचार को विनियमन के साथ एकीकृत करना चाहिए और तेजी से बदलते वित्तीय परिदृश्य में रणनीतिक सतर्कता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- वित्त मंत्री का संदेश स्पष्ट है: भारत को अपने वैश्विक आर्थिक प्रभाव को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए, लचीला बने रहना चाहिए और उभरती हुई मौद्रिक संरचनाओं का लाभ उठाना चाहिए।

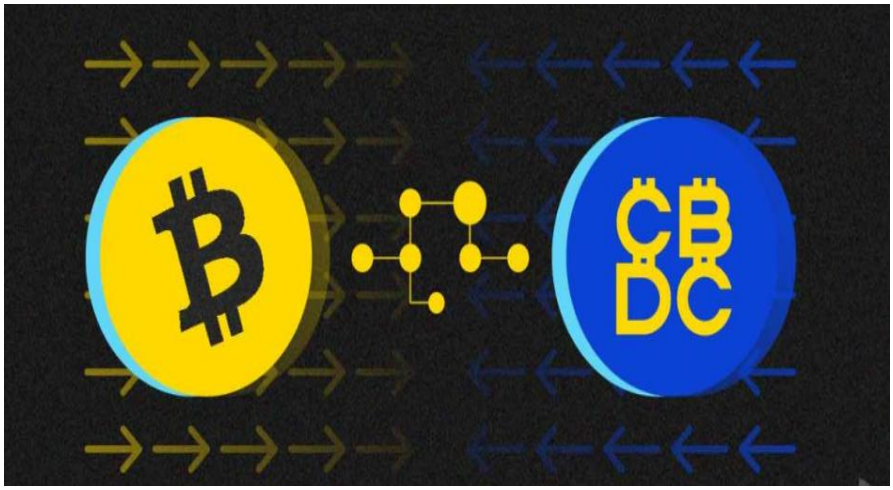

IAS-PCS Institute
Result Mitra
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

यूपीएससी प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: सीबीडीसी (केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएँ) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई डिजिटल मुद्राएँ हैं।
2. इनकी कानूनी स्थिति देश की फिएट मुद्रा के समान ही है।
3. ये मुख्य रूप से निजी निगमों द्वारा सीमा पार भुगतान की सुविधा के लिए जारी की जाती हैं।
4. आरबीआई वर्तमान में भारत में सीबीडीसी का संचालन कर रहा है।

ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं?

(A) केवल 1, 2 और 4
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (A)

व्याख्या:

1. केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी, निजी निगमों द्वारा नहीं।
2. वैध मुद्रा, फिएट मुद्रा के समान।
3. निजी निगम CBDC जारी नहीं करते; वे निजी क्रिप्टोकरेंसी जारी कर सकते हैं।
4. RBI भारत में CBDC का परीक्षण कर रहा है।

प्रश्न 2: स्टेबल कॉइन्स हैं:

(A) मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए स्थिर परिसंपत्ति से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी
(B) सरकार समर्थित वैध मुद्राएँ
(C) बिटकॉइन जैसी अत्यधिक अस्थिर क्रिप्टोकरेंसी
(D) केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राएँ

उत्तर: (A)

स्पष्टीकरण: स्टेबल कॉइन्स को अस्थिरता कम करने और डिजिटल भुगतान को सुगम बनाने के लिए फिएट मुद्रा या सोने जैसी परिसंपत्तियों से जोड़ा जाता है।

प्रश्न 3: भारत की वर्तमान क्रिप्टोकरेंसी नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

1. भारत में निजी क्रिप्टोकरेंसी पूरी तरह से वैध हैं।
2. आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों (VDA) से जुड़े लेनदेन पर कर लगता है।
3. RBI अपने स्वयं के CBDC का संचालन करते हुए निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करता है।

सही उत्तर: (B) केवल 2 और 3

स्पष्टीकरण:

1. भारत में निजी क्रिप्टोकरेंसी वैध नहीं हैं।
2. लेनदेन पर कर लगता है।
3. RBI निजी क्रिप्टोकरेंसी के प्रति आगाह करते हुए CBDC को बढ़ावा देता है।

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
9235313184, 9235440806

प्रश्न 4: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रों को:

(A) सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए।

(B) स्टेबल कॉइन या जोखिम बहिष्करण जैसी नई मौद्रिक संरचनाओं को अपनाना चाहिए।

(C) फिएट मुद्रा को स्टेबलकॉइन से बदलना चाहिए।

(D) वैश्विक क्रिप्टो रुझानों से पूर्ण अलगाव बनाए रखना चाहिए।

IAS-PCS Ins

उत्तर: (B)

स्पष्टीकरण:वैश्विक वित्तीय प्रणालियों से बहिष्कृत होने से बचने के लिए राष्ट्रों को स्टेबलकॉइन जैसे नवाचारों से जुड़ना चाहिए।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: भारत की मौद्रिक संप्रभुता पर स्टेबलकॉइन और डिजिटल मुद्रा नवाचारों के प्रभावों पर चर्चा करें।(150 words)

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmi resultmitra.com 9235313184, 9235440806